पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 496/2023

=====
रेशम देवी, पति- सत्येन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवास- ग्राम- रामदशा, थाना- मोहनपुर, जिला- गया,
वर्तमान पता- ग्राम- बड़ा गुरारू, थाना- गुरारू, जिला- गया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. गुप्ता प्रसाद अग्रवाल, पिता- स्व. लखन लाल, निवासी- ग्राम- बड़ा गुरारू, थाना-गुरारू,
जिला- गया।
2. अर्जुन प्रसाद अग्रवाल, पिता- स्व. लखन शाव, निवासी-बाके बाजार, थाना गुरारू, जिला-
गया।
3. देव लाल यादव, पुत्र-स्व. रामदेव प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम- बड़ा गुरारू, थाना- गुरारू,
जिला- गया।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====
उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए : श्री नगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता

=====
याचिका - उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसे उप-न्यायाधीश ने पारित
किया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत दायर की गई संपत्ति के
तात्कालिक पुनः कब्जे के लिए याचिका को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता शीर्षक मुकदमे में पक्षकार हैं और प्रतिवादी नंबर 1 संपत्ति के मालिक थे।
प्रतिवादी नंबर 1 (प्रतिवादी संख्या 1) ने एक पंजीकृत शर्तीय बिक्री विलेख निष्पादित किया था
जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 के लिए पुनर्खरीद का विकल्प था। समय सीमा समाप्त होने के बाद,
याचिकाकर्ता ने अधिकार और शीर्षक के निर्धारण के लिए एक शीर्षक मुकदमा दायर किया।

इस बीच, प्रतिवादी नंबर 1 ने संपत्ति को बेच दिया। परीक्षण अदालत ने प्रतिवादियों को संपत्ति को हस्तांतरित करने और याचिकाकर्ता के कब्जे को परेशान करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 3 ने उसे संपत्ति से बलात्कृत तरीके से निकाल दिया, उसे और उसके पति को मारा, दुकान को लूटा, और मोबाइल फोन, नकद और आभूषण ले गए। फिर उसने निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत पुनः कब्जे के लिए याचिका दायर की, जिसे परीक्षण अदालत ने खारिज कर दिया।

याचिका को खारिज करते हुए, सीखा न्यायालय केवल इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि याचिका धारा 151 के तहत दायर की गई थी और यदि वैकल्पिक उपचार मौजूद हैं तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और यह भी कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे में कब्जे की वसूली के लिए राहत नहीं मांगी।

निर्णय - कानून का शासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उन्हें उल्लंघन करने का साहस नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह समाज में अराजकता का कारण बनेगा। - याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए वैकल्पिक उपचार का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। अदालत की अंतर्निहित शक्ति हमेशा ऐसे मामलों में उपलब्ध रहती है और इसे गलत को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। (पैरा 9)

सीखा न्यायालय को निर्देश दिया गया है कि पुलिस की मदद से याचिकाकर्ता को कब्जा बहाल कराया जाए, यदि आवश्यक हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस न्यायालय के आदेशों का पालन करने में सभी सहयोग किया जाए। (पैरा 11)

याचिका स्वीकार की गई। (पैरा 12)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 22-07-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना गया।

2. यह याचिका वादी/याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान उप-न्यायाधीश-5, गया द्वारा टाइटल सूट संख्या 150/2016 में पारित दिनांक 21.01.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता शीर्षक मुकदमे में वादी है और प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे वाली संपत्ति का मालिक था। प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी/याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 07.07.2009 को एक पंजीकृत सशर्त बिक्री विलेख निष्पादित किया, जिसमें पांच वर्षों के भीतर यानी 06.07.2014 तक उसी प्रतिफल पर इसे पुनः खरीदने का अधिकार सुरक्षित रखा गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 ने 06.07.2014 तक मुकदमे की संपत्ति को पुनः नहीं खरीदा, इसलिए वादी/याचिकाकर्ता पूर्ण रूप से मालिक बन गई। वादी/याचिकाकर्ता ने मुकदमे की भूमि पर दो कमरे और एक दुकान का निर्माण किया और वादी/याचिकाकर्ता और उसके पति ने उक्त कमरों में रहना शुरू कर दिया और वादी/याचिकाकर्ता के पति ने दुकान से व्यवसाय करना शुरू कर दिया। जब प्रतिवादी सं.1/प्रतिवादी सं.1 द्वारा वादी/याचिकाकर्ता के स्वामित्व को अस्वीकार कर दिया गया, तब वादी/याचिकाकर्ता ने दावे

वाली संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व की घोषणा के लिए शीर्षक वाद सं.150/2016 दायर किया। इस बीच, प्रतिवादी सं.1/प्रतिवादी सं.1 ने दावे वाली संपत्ति प्रतिवादी सं. 2/प्रतिवादी सं.2 को पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 06.01.2015 के अनुसार बेच दी और प्रतिवादी सं.2/प्रतिवादी सं.2 ने दावे वाली संपत्ति प्रतिवादी सं.3/प्रतिवादी सं.3 को पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 15.09.2016 के अनुसार बेच दी। तीनों प्रतिवादियों को क्रमशः प्रतिवादी सं.1, 2 और 3 बनाया गया है। प्रतिवादी सं.2 और 3/प्रतिवादी सं.2 और 3 उपस्थित हुए और अपने शीर्षक वाद में अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि उपरोक्त पंजीकृत सशर्त बिक्री विलेख दिनांक 07.07.2014 वास्तव में एक उपभोक्ता बंधक विलेख था और प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 1,30,000/- रुपये की बंधक राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था। वादी/याचिकाकर्ता ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया, जिस पर सुनवाई हुई और दिनांक 08.09.2016 के आदेश के अनुसार अनुमति दी गई और प्रतिवादियों/प्रतिवादियों को किसी भी तरह से संपत्ति को अलग करने और वादी/याचिकाकर्ता के कब्जे को बाधित न करने से रोक दिया गया। वादी/याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या। 3 और उसके बेटे ने अवैध तरीकों से वादी/याचिकाकर्ता को वाद की संपत्ति से जबरन बेदखल कर दिया, वादी/याचिकाकर्ता और उसके पति की पिटाई की और उसे जबरन खाली कराकर वाद की संपत्ति से बेदखल कर दिया और वादी/याचिकाकर्ता की दुकान लूट ली और वाद परिसर से कई मोबाइल सेट, नकदी और गहने छीन लिए। 08.12.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गया के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वादी/याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.09.2016 के आदेश के उल्लंघन के लिए विद्वान निचली अदालत के समक्ष एक विविध मामला भी दायर किया, लेकिन उक्त याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके बाद, वादी/याचिकाकर्ता ने वाद की संपत्ति पर तत्काल कब्जे की बहाली के लिए 23.12.2020 को संहिता की धारा 151 के तहत एक और याचिका दायर

की प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर दिया गया और पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को दिनांक 21.01.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. वादी/याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट का आदेश टिकने लायक नहीं है क्योंकि इसे तथ्यों और परिस्थितियों तथा लागू कानून पर विचार किए बिना पारित किया गया है। न्यायालय ने अपने स्वयं के दिनांक 08.09.2016 के आदेश पर विचार किए बिना ही इसे पारित कर दिया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिका को खारिज करते समय, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने केवल इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि याचिका संहिता की धारा 151 के तहत दायर की गई थी और यदि वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर भी कि वादी ने मुकदमे में कब्जे की वसूली के रूप में राहत नहीं मांगी है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रा.) लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट (1996) 4 एससीसी 622 में दी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जहां निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया जाता है, वहां न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह नीति के रूप में गलत को सही करे और गलत कार्य को जारी न रहने दे। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, यह माना गया, न केवल ऐसे मामले में उपलब्ध है बल्कि न्याय के हित में गलत को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना बाध्य है। कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उक्त कार्रवाई आवश्यक थी। विद्वान वकील ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **ऑल बंगाल एक्साइज लाइसेंसीज एसोसिएशन बनाम रेघबेंद्र सिंह एवं अन्य** के मामले का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट (2007) 11 एससीसी 374: एआईआर 2007 एससी 1386 में की गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अदालतों ने कई फैसलों में माना है कि जहां किसी पक्ष के खिलाफ निरोधक आदेश या

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए कुछ किया गया है, नीति के तौर पर अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह गलत को सही करे और गलत काम को जारी न होने दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे माना कि ऐसे मामले में संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति न केवल उपलब्ध होगी बल्कि न्याय और जनहित में उस तरीके से इसका प्रयोग नहीं करना गलत है। यह भी माना गया है कि न्यायिक नीति के मामले में, न्यायालय को इस तरह की परिस्थितियों में खुद को मूर्ख बनने से बचाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करके किए गए गलत काम को रद्द करने में न्यायालय शक्तिहीन है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और आदेश पारित कर दिया जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादी सं. 3/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आरोपित आदेश संधारणीय है और मामले में सभी तथ्यों और लागू कानून पर विचार करने के बाद पारित किया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी सं. 3/प्रतिवादी सं. 3 ने प्रतिवादी सं. 2/प्रतिवादी सं. 2 से भूमि खरीदी, जिसे निषेधाज्ञा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि दिनांक 08.09.2016 के आदेश में केवल इस तथ्य का उल्लेख है कि प्रतिवादी सं. 2/प्रतिवादी सं. 2 ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया लेकिन इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई है कि उसे वैध रूप से नोटिस दिया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि बेदखली और कब्जे की वसूली के संबंध में शिकायत में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रतिवादी सं. 2 और 3/प्रतिवादी सं. प्रतिवादी सं. 1/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिक्री के बारे में पता चलने के बाद भी मूल शिकायत में धारा 2 और 3 को चुनौती नहीं दी गई है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि ऐसी परिस्थितियों में संहिता की धारा 151 का कोई आवेदन नहीं हो सकता है जब वादी/याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं। विद्वान वकील ने आगे कहा कि इसके अलावा, प्रतिवादी सं. 2/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा बिक्री

विलेख के निष्पादन के बाद भूमि प्रतिवादी सं. 3/प्रतिवादी सं. 3 के कब्जे में आई और यहां तक कि वादी/याचिकाकर्ता ने भी मुकदमे की संपत्ति से अपने बेदखली की कोई तारीख नहीं बताई है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वादी/याचिकाकर्ता के पति ने 15 लाख रुपये लिए। प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 से 70,000/- रुपये की राशि वसूल की और उसके बाद प्रतिवादियों ने शेष राशि 1,30,000/-रुपये का भुगतान करने के लिए कई प्रयास किए और प्रतिवादियों के प्रयासों के बावजूद वादी/याचिकाकर्ता को पैसे नहीं मिले। दूसरी ओर, यदि निर्धारित अवधि के भीतर पैसे वापस नहीं किए गए और भुगतान करने के लिए वादी/याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस दिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

6. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतिकरण पर गहनता से विचार किया है और अभिलेख का भी बारीकी से अध्ययन किया है। वादी/याचिकाकर्ता 07.07.2009 की पंजीकृत सशर्त बिक्री विलेख के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार का दावा करती है, जिसके संचालन से वह कब्जे का भी दावा करती है। हालांकि इस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा विवादित किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 हैं, जिन्होंने यह दावा करते हुए अपने लिखित बयान दायर किए हैं कि यह सशर्त बिक्री का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक दस्तावेज है। उपभोक्ता बंधक का दस्तावेज। लेकिन मामले के उक्त पहलू पर पूरी सुनवाई के बाद ही फैसला किया जाएगा और वर्तमान उद्देश्य के लिए दोनों दस्तावेज, चाहे वह सशर्त बिक्री के लिए दस्तावेज हो या उपभोक्ता बंधक के लिए, इन दस्तावेजों का प्रभाव यह है कि कब्जा उस व्यक्ति को जाएगा जिससे विचार प्राप्त होता है और वर्तमान मामले में उक्त व्यक्ति वादी/याचिकाकर्ता है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि उक्त दस्तावेज पर कार्रवाई नहीं की गई है और यह कागज पर ही रह गया है। बल्कि निष्पादन को स्वीकार किया जाता है। बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख से मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के बारे में प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 का जो भी दावा है, वह विश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि प्रतिवादी

संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दावा किए गए कब्जे को दिखाने के लिए कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

7. इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बेदखली की कोई तारीख नहीं दी गई है। हालांकि, पूरक हलफनामे के माध्यम से, वादी/याचिकाकर्ता द्वारा कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाए गए हैं और ऐसा ही एक दस्तावेज गुरारू पी.एस. केस नंबर 138/2020 की प्रति है जिसमें घटना की तारीख 07.12.2020 बताई गई है। इसलिए, बेदखली की तारीख का उल्लेख नहीं करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक प्रतिवादियों का दावा है कि प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 उस प्रासंगिक तारीख को पक्ष नहीं था जब दिनांक 08.09.2016 का आदेश पारित किया गया था, अदालत ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 को जानकारी थी। प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अपने भाई हैं और यह भी एक सुसंगत तथ्य है जिसे प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 को ज्ञान प्रदान करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिन्होंने 04.01.2017 को अपना लिखित बयान दाखिल किया था। **सावित्री देवी बनाम राजो देवी एवं अन्य** के मामले में, **2006 (3) पीएलजेआर 454** में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि यदि किसी पक्ष ने निषेधाज्ञा की सूचना प्राप्त करने के बाद जानबूझकर और स्वेच्छा से स्थिति को बदल दिया है ताकि न्यायालय की अनुमति के बिना निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को निष्फल और निष्फल बनाया जा सके, तो यह निश्चित रूप से न्यायालय तक पहुँचने का प्रयास करने और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा। यदि जांच में यह पाया जाता है कि निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल करने के बाद निर्माण किया गया था, तो न्यायालय निषेधाज्ञा की तिथि पर **यथास्थिति** बहाल करने के लिए बाध्य है, भले ही न्यायालय द्वारा कोई **यथास्थिति** आदेश न

दिया गया हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया निष्फल हो जाएगी। लिखित बयान में भी, प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया है कि वादी/याचिकाकर्ता के पास वाद संपत्ति पर अनुमेय कब्जा है, हालांकि उन्होंने वाद संपत्ति पर अधिकार और शीर्षक का दावा किया है, साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि 06.07.2024 तक उपभोग बंधक अभी भी विद्यमान है और इस बात से इनकार किया है कि 01.08.2014 को कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद संपत्ति पर वादी/याचिकाकर्ता के शीर्षक से कभी इनकार नहीं किया। लिखित बयान में की गई प्रस्तुति वादी/याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दे को अंतिम रूप देती है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 का विक्रेता है और प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 को मिलने वाला कोई भी अधिकार केवल प्रतिवादी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है।

8. जहां तक प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत किए गए इस कथन का संबंध है कि वादी/याचिकाकर्ता बिक्री विलेख के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर रहा है या संशोधन के माध्यम से वादपत्र में कब्जे की वसूली की मांग नहीं कर रहा है, यह वादी/याचिकाकर्ता द्वारा अधिकारों के दावे और उसके प्रवर्तन के संबंध में है और इसे वादी/याचिकाकर्ता के मौजूदा अधिकार को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है जिसे उसने स्वीकृत दस्तावेज, सशर्त बिक्री बीज/उपभोक्ता बंधक विलेख के माध्यम से प्राप्त किया है। इसके अलावा, अभी तक उचित आवेदन प्रस्तुत करने जैसा चरण पार नहीं किया गया है और इससे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता।

9. कानून के शासन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के निर्देशों का पालन करे और कभी भी उनका उल्लंघन करने का साहस न करे अन्यथा इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी। वादी/याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने

सही ढंग से प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी/याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करने के लिए वैकल्पिक उपाय का लाभ न उठाने का कोई आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति ऐसे मामलों में हमेशा उपलब्ध होती है और गलत को पूर्ववत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना है कि जब चीजें ऐसी स्थिति में आ जाती हैं और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सीधे तौर पर गलतियां की जाती हैं, तो न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी गलतियों को ठीक करें।

सेंचुरी फ्लोर मिल्स लिमिटेड बनाम एस. सुप्पियाह एवं अन्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे **एआईआर 1975 मद्रास 270** में रिपोर्ट किया गया था और इस निर्णय का पैराग्राफ संख्या 8 इस प्रकार है:-

“8. हमारी राय में, धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ व्यापक हैं और किसी सीमा के अधीन नहीं हैं। जहाँ किसी पक्ष के विरुद्ध स्थगन आदेश या निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए, अवज्ञा में कुछ किया गया है, वहाँ नीति के रूप में न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह गलत को सही करे और गलत काम को जारी न रहने दे। हमारी राय में, ऐसे मामले में अंतर्निहित शक्ति न केवल उपलब्ध होगी, बल्कि न्याय के हित में इसका प्रयोग उसी तरह से किया जाना चाहिए। धारा 151 से अलग भी, हमें यह देखना चाहिए कि न्यायिक नीति के मामले में, न्यायालय को इस तरह की परिस्थितियों में खुद को मूर्ख बनाने से बचना चाहिए, यह मानकर कि वह न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा में किए गए गलत काम को पूर्ववत करने में शक्तिहीन है। लेकिन इस मामले में ऐसा करना उस सीमा तक

आवश्यक नहीं है, जितना हम मानते हैं कि धारा 151 सी.पी.सी. के तहत शक्ति उपलब्ध है।”

सुजीत पाल बनाम प्रबीर कुमार सन एवं अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसे एआईआर 1986 कैल 220 में रिपोर्ट किया गया था, को भी कानून के उपरोक्त प्रावधान पर संदर्भित किया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 12 और 13 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है, जो इस प्रकार है:-

“12. हमारा जो दृष्टिकोण है, उसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मैग्ना बनाम रुस्तम, एआईआर 1963 राज 3 के निर्णय से समर्थन मिलता है। उस मामले में, यह देखा गया है कि यद्यपि संहिता की धारा 39, नियम 2(3) अवज्ञा के दोषी पक्ष पर जुर्माना लगाने के विषय पर विस्तृत है, यह उस पक्ष को कोई राहत प्रदान नहीं करता है जिसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि इस तरह के आदेश का उद्देश्य दूसरे पक्ष द्वारा आक्रमण की धमकी के खिलाफ एक पक्ष के अधिकारों की रक्षा करना है, और यदि निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ऐसे अधिकारों पर आक्रमण किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष को राहत केवल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का आह्वान करके दी जा सकती है।

सिविल पी.सी. की धारा 151 के तहत न्यायालय

13. हरि नंदन बनाम एस.एन. पंडिता, एआईआर 1975 ऑल 48 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया है जो हमारा है, अर्थात्, जब किसी पक्ष को निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा करके बेदखल कर दिया जाता है, तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए

न्याय के उद्देश्य से ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो पीड़ित पक्ष के साथ किए गए अन्याय को समाप्त कर दे।"

दिल्ली विकास प्राधिकरण (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है और पैराग्राफ संख्या 18, 19 और 20 इस प्रकार हैं: -

"18. उपरोक्त सिद्धांत को सिविल न्यायालयों द्वारा जारी निषेधाज्ञा के आदेशों के उल्लंघन के मामले में भी लागू किया गया है। क्लार्क बनाम चैंडबर्न [1985 (1) ऑल.ई.आर. 211] में, सर रॉबर्ट मेगारी वी-सी ने कहा:

"मुझे इस प्रस्ताव के लिए किसी अधिकारी का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है कि न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना न्यायालय की अवमानना के रूप में दंडनीय है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी अवज्ञा को उचित रूप से अवैध कहा जा सकता है। यदि ऐसी अवज्ञा से आदेशित व्यक्ति यह दावा करते हैं कि उन्होंने दूसरों के अधिकारों और दायित्वों पर वैध रूप से कुछ प्रभाव डाला है, तो मैं नहीं समझ सकता कि यह क्यों कहा जाना चाहिए कि यद्यपि वे जो कुछ भी कर रहे थे उसके लिए न्यायालय की अवमानना के लिए दंड के पात्र थे, फिर भी वे कार्य वैध रूप से किए गए थे। बेशक, यदि कोई कार्य किया जाता है, तो यह केवल यह इंगित करके रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह कानून का उल्लंघन करके किया गया था। यदि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके कोई बैठक आयोजित की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बैठक ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं माना गया है। लेकिन कानून का उल्लंघन करके जो कुछ किया गया है, उसके कानूनी परिणाम स्पष्ट रूप से अवैधता से बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सिद्धांत रूप से जो लोग निषेध का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह दावा करने का

अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके उल्लंघन के परिणाम अच्छे हैं, और उन्हें उत्पन्न करने वाली अवैधता से दूषित नहीं हैं।"

19. सेंचुरी फ्लोर मिल्स लिमिटेड बनाम एस. सुप्पियाह एवं अन्य [ए.आई.आर.1975 मद्रास 270] और सुजीत पाल बनाम प्रबीर कुमार सन [ए.आई.आर.1986 कलकत्ता 220] में मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के निर्णय भी इसी प्रभाव के हैं। सेंचुरी फ्लोर मिल लिमिटेड में, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना था कि जहां कोई कार्य स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करके किया जाता है, वहां नीति के रूप में, गलत को सही करना और गलत काम को जारी न रहने देना न्यायालय का कर्तव्य है। यह माना गया कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न केवल ऐसे मामले में उपलब्ध है, बल्कि न्याय के हित में गलत को पूर्ववत करने के लिए इसका प्रयोग करना भी बाध्य है। यह एक ऐसा मामला था जहां निषेधाज्ञा के आदेश के विपरीत बैठक आयोजित की गई थी इसने पक्षों को उसी स्थिति में वापस ला दिया, जिसमें वे अंतरिम आदेश की तामील से ठीक पहले थे।

20. सूरज पाल मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। वहां प्रतिवादी ने निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करते हुए वादी को जबरन बेदखल कर दिया और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। न्यायालय ने पुलिस की सहायता से वादी को कब्जा वापस दिलाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि कोई भी तकनीकी बात न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय करने से नहीं रोक सकती। न्यायालय ने कहा कि आदेश 39 के नियम 2-ए का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पीड़ित पक्ष को कब्जा वापस दिलाने के लिए ऐसा अनिवार्य निर्देश दिया

जाएगा। न्यायालय ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक था।

सुशील कुमार डे बिस्वास एवं अन्य बनाम अनिल कुमार डे बिस्वास एवं अन्य, (2015) 3 एससीसी 461 में दर्ज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है। उक्त मामले में प्रतिवादी/वादी ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी को परिसर से बेदखल कर दिया, हालांकि यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी के पास मुकदमे की संपत्ति के कुछ हिस्से का कब्जा था और कब्जे की बहाली के लिए संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी/वादी को अपीलकर्ता/प्रतिवादी का कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसी तरह की परिस्थितियों में, **मीरा चौहान बनाम हर्ष बिश्रोई** के मामले में, (2007) 12 एससीसी 201 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मामले के दिए गए तथ्यों में संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन पर विचार किया जा सकता है और कब्जे की बहाली के रूप में निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के लिए संहिता की धारा 151 के तहत शक्ति अब मौजूद नहीं है।

10. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, स्थापित कानून के आलोक में, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान उप-न्यायाधीश-5, गया द्वारा शीर्षक वाद संख्या 150/2016 में पारित दिनांक 21.01.2023 का विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे अलग रखा जाता है और वादी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 23.12.2020 की याचिका को अनुमति दी जाती है।

11. विद्वान ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस की मदद से वादी/याचिकाकर्ता को कब्जा वापस दिलाया जाए। गया के वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सभी प्रकार का सहयोग सुनिश्चित करें।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान सिविल विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

13. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

बालमुकुन्द/-